पुणे में निर्मित होने जा रही नांदेड़ सिटी का रविवार को भूमिपूजन दीप प्रजवलित कर करते हुए मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, केन्द्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटिल, जलसंसाधन मंत्री अजीत पवार, वनमंत्री बबनराव पाचपुते, ऊर्जामंत्री दिलीप वलसे पाटिल, मगरपट्टा कंपनी के अध्यक्ष सतीश मगर व अन्य चित्र में दिखाई दे रहे हैं.

किसानों के एक साथ आने पर मगरपट्टा पैटर्न पर प्रकल्प बनाए जाएंगे : मुख्यमंत्री

अब टाउनशिप्स को मिलेगा 1% F.S.I.

पुणे, 1 जून (वि.प्र.)

राज्य की समस्त टाऊन शिप्स को अब आधे प्रतिशत की बजाए एक प्रतिशत एफ.एस.आई. (चटई क्षेत्र निर्देशांक) देने का निर्णय लिया गया है. यह जानकारी पुणे में मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने रविवार को दी. इस कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार ने राय प्रगट की और कहा कि राज्य सरकार इस निर्णय को लागू करते समय समाज के गरीब तबकों को घर मिलें इसके लिए टाऊनशिप्स में कुछ घर आरक्षित रखने के नियम बनाए. इससे समाज में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी.

मगरपट्टा टाऊनशिप डेवलपमेंट एन्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी पुणे द्वारा पुणे जिले में किसानों को साथ लेकर द्वितीय टाऊनशिप निर्मित करने जा रही है. इस टाऊनशिप 'नांदेड़ सिटी' का भूमिपूजन कार्यक्रम शरद पवार के हाथों आज संपन्न हुआ. इस समय मुख्यमंत्री श्री देशमुख, उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटिल, ऊर्जा मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, जल संसाधन मंत्री अजीत पवार, वनमंत्री बबनराव पाचपुते, सांसद सुप्रिया सुले, पुणे की महापौर राजलक्ष्मी भोसले, कंपनी के अध्यक्ष सतीश मगर आदि उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को कंपनी में शेयर होल्डर बनाकर निर्मित की जा रही टाऊनशिप एक आधुनिक कल्पना है. ➡ शेष पेज 10 पर

किसानों के एक साथ...

(पेज 1 से आगे)

ऐसे समय किसानों को सुविधाएं-सहूलियतें देने में सरकार नहीं हटेगी. साथ ही आधे प्रतिशत की जगह एक प्रतिशत एफ.एस.आई. अब दिए जाने से सरकार को भी लाभ मिलेगा. ऐसी अपेक्षा मुख्यमंत्री ने प्रगट की.

राज्य में गुंठेवारी की वजह से कैसा भी इस्तेमाल किया गया ? मगर अब इस अंधाधुध इस्तेमाल को राज्य सरकारने रोकने का निर्णय लिया है. मगरपट्टा पैटर्न को यहीं तक सीमित न रखकर जहां किसान एक साथ सामने आएंगे वहां प्रकल्प बनाए की उपेक्षा मुख्यमंत्री ने व्यक्त की. किसानों को सबल बनाने में यह पैटर्न सफल सिद्ध हुआ है. निजी टाउनशिप में किसानों का शोषण होता है.

राज्य के योजनाबद्ध विकास के लिए मगरपट्टा सिटी नांदेड़ सिटी जैसी योजनाओं की हम सहायता करते हैं. मगर इस समय शरद पवार की ही यह योजना है तो लगता है जैसे यह हमारी ही है. मगर लोगों की यह गलत फहमी सही होती तो और खुशी होगी. यह कहते हुए शरद पवार ने अपने भाषण में साफ नकार दिया कि मगरपट्टा योजना उनकी है. उन्होंने मीडिया से अपेक्षा की कि इस मामले को साकारात्मक नजरिए से देखा जाए. किसानों की दूसरी पीढ़ी ने दिखा दिया है कि किसान का पुत्र खेती से बाहर होकर ही उद्योगपति बन सकता है. शहरीकरण का जबरदस्त नुकसान शहर के

आर.आर. पाटिल ने अपने भाषण में कहा कि सेज, टाउनशिप आदि समय की जरूरतें हैं. राज्य एवं देश में ऐसे पैटर्न सफल होने चाहिए. इस पैटर्न से किसानों की जीवन भर की वित्तीय परेशानियां दूर हो जाएंगी.

पालकमंत्री अजीत पवार ने मगरपट्टा सिटी, नांदेड सिटी जैसी योजनाओं की पुणे जिले के अन्य इलाकों में चलाने की इच्छा जताते हुए कहा कि योजना में किसी पर अन्याय न हो इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा.

इस समय कंपनी के अध्यक्ष सतीश मगर ने अपने प्रास्तविक भाषण में एक फिल्म के जरिए जानकारी दी तथा संचालक प्रकाश पायगुडे ने किया.

रेत माफिया पर कड़ी कार्रवाई

राज्य की नदियों से रेती निकाल लेने से नदियों के किनारे सूख रहे हैं, साथ ही बालू ढूलाई करनेवाले ट्रकों से रास्तों की हालत खराब हो रही है. इसी के साथ रेत माफियाओं की लोगों में दहशत भी बढ़ रही है. इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य में रेत खनन पर पाबंदी लगाने के इरादे हैं. कार्यक्रम में अजीत पवार के इस वक्तव्य का मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में समर्थन किया.